इकाई 3 भारतीय अनुभव

संरचना

3.0 प्रस्तावना

3.1 उद्देश्य

3.2 मुक्त एवं दूरस्थ अधिगम द्वारा शिक्षा

- 3.2.1 शिक्षा का लोकतांत्रिकरण बनाम दूरस्थ शिक्षा कार्यक्रम
- 3.2.2 मुक्त विश्वविद्यालय व्यवस्था
- 3.2.3 मुक्त विद्यालय
- 3.2.4 अध्यापक शिक्षा

3.3 समस्याएँ एवं चुनौतियाँ

- 3.3.1 द्विपद्धतीय विश्वविद्यालय
- 3.2.2 एकल पद्धतीय विश्वविद्यालय

3.4 सारांश

3.5 ''अपनी प्रगति जाँचें'' प्रश्नों के उत्तर

3.6 संदर्भ ग्रंथ

3.7 इकाई अंत अभ्यास

3.0 प्रस्तावना

जैसा कि इकाई-1 में हम चर्चा कर चुके हैं कि भारत में मुक्त एवं दूरस्थ शिक्षा पद्धति विश्वविद्यालय स्तर पर आरंभ होकर विद्यालय स्तर की तरफ बढ़ी जो स्पष्टतः अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मुक्त एवं दूरस्थ शिक्षा के इतिहास में सामान्य विशेषता रही है। परंतु पत्राचार पाठ्यक्रमों के माध्यम से दूरस्थ शिक्षा की शुरूआत के भारत में दोहरे उद्देश्य थे। प्रथम, उच्च शिक्षा के इच्छुकों के दबाव समूह को पत्राचार शिक्षा पाठ्यक्रमों की तरफ भेजना जो कि कम खर्चीले हैं; तथा दूसरा, समता एवं समानता के बढ़े हुए अवसरों द्वारा उच्च शिक्षा का लोकतांत्रिकरण करना। हम इन सभी पहलुओं के बारे में गहन चर्चा कर चुके हैं तथा इस संदर्भ में दी गई विभिन्न शैक्षिक संगठनों तथा नीतिगत दस्तावेजों में अनुशंसाओं एवं वक्तव्यों के बारे में उचित विवरण दे चुके हैं जो इस संबंध में समुचित आधार प्रदान किए हैं।

एक वैश्विक तथ्य यह है कि द्वितीय विश्वयुद्ध के बाद शिक्षा के लोकतांत्रिकरण हेतु किए गए प्रयासों के कारण, दूरस्थ शिक्षा का प्रसार विश्व के सभी देशों में हुआ तथा यह तंत्र एक शताब्दी में विभिन्न अवस्थाओं से गुजरा। इसकी अवधारणा एवं प्रकार्य, सामान्यतः संप्रेषण तकनीकी तथा मुख्यतः शिक्षा तकनीकी के विकास से बहुत अधिक संबंधित रहे हैं।

हालांकि हम इकाई-4 में वैश्विक अभ्यासों के बारे में गहन चर्चा करेंगे। इस इकाई में आपको दूरस्थ शिक्षा के भारतीय अनुभवों के बारे में वर्णन प्रस्तुत किया जाएगा। इस संदर्भ में, इस इकाई को आगे पढ़ने से पहले हम आपको यह सुझाव देना चाहेंगे कि आप इकाई-1 के अनुभाग 1.3 में दिए गए नीति परिप्रेक्ष्यों के बारे में पुनः जानकारी प्राप्त कर लें।

3.1 उद्देश्य

इस इकाई के अध्ययन के पश्चात आपः

- मुक्त एवं दूरस्थ शिक्षा के भारतीय अनुभव को समझ सकेंगे;
- मुक्त एवं दूरस्थ शिक्षा के राष्ट्रीय स्तर पर परिदृश्य का वर्णन कर सकेंगे;
- भारत में मुक्त एवं दूरस्थ शिक्षा के मुद्दों, समस्याओं तथा चुनौतियों का विश्लेषण कर सकेंगे।

3.2 मुक्त एवं दूरस्थ अधिगम द्वारा शिक्षा

हमें यह ज्ञात है कि भारतीय संविधान ने लोकतंत्र को सामाजिक व्यवस्था के महत्त्वपूर्ण अंश के रूप में अपनाया है। शिक्षा के लोकतांत्रिकरण द्वारा ही समाज में लोकतांत्रिक व्यवस्था अस्तित्व में रह सकती है। सैद्धांतिक तौर पर यह बल दिया गया था कि उच्च शिक्षा के इच्छुकों समेत सभी को समान अवसर प्रदान करने हेतु राष्ट्र में शिक्षा को लोकतांत्रिक मूल्यों को अपनाने चाहिए। सरकारी स्तर पर परंपरागत शिक्षा पद्धति के प्रसार में आने वाली कठिनाइयों के कारण तथा सभी स्तरों पर पारंपरिक शिक्षा की कमियों के कारण सामान्य शिक्षा एवं मुख्यतः उच्च शिक्षा का लोकतांत्रिकरण करना आज तक अधूरा सपना ही रह गया है।

3.2.1 शिक्षा का लोकतांत्रिकरण बनाम दूरस्थ शिक्षा कार्यक्रम

स्वतंत्रता के पश्चात उच्च शिक्षा की मांग तथा इसके परिणामस्वरूप शैक्षिक सुविधाओं में बढ़ोतरी ने योजना आयोग को भारत में शिक्षा के लोकतांत्रिकरण के लिए विभिन्न रणनीतियों के सृजन करने के लिए बाध्य किया। इसलिए दूरस्थ शिक्षा की दिशा में भारत सरकार की नीति, साठ के दशक के आरंभ से ही अनुकूल रही है। भारत में दूरस्थ शिक्षा की जड़ें, सभी स्तरों पर शिक्षा के लोकतांत्रिकरण के लिए शिक्षा के अन्य विकल्पों को ढूंढने एवं बढ़ाने के लिए किए गए राष्ट्रीय प्रयासों में आ रही विभिन्न समस्याओं, माँग एवं चुनौतियों में देखी जा सकती है। इकाई-1 के भाग 1.3 में भारत सरकार की दूरस्थ शिक्षा के प्रति अनुकूल नीतियों एवं निर्देशों के बारे में आपको अच्छे ढंग से समझाया जा चुका है। इकाई-1 के भाग 1.5 में दूरस्थ शिक्षा द्वारा शिक्षा के लोकतांत्रिकरण के बारे में चर्चा कर चुके हैं। दूसरे शब्दों में, शिक्षा के सभी स्तरों पर, शिक्षा के लोकतांत्रिकरण में दूरस्थ शिक्षा की भूमिका एवं महत्त्व के बारे में इसमें समझाया जा चुका है। इसके आगे इकाई-1 में उप-अनुभाग 1.2.2 में हमने आपको भारत में मुक्त एवं दूरस्थ शिक्षा के बारे में एक परिदृष्टि प्रस्तुत किया था।

इसलिए, अग्रिम अनुभागों में, हम मुक्त विश्वविद्यालयी व्यवस्था, मुक्त विद्यालय तथा मुक्त एवं दूरस्थ शिक्षा द्वारा अध्यापक शिक्षा के बारे में चर्चा करेंगे।

3.2.2 मुक्त विश्वविद्यालय व्यवस्था

भारत में मुक्त विश्वविद्यालय की स्थापना को ब्रिटेन में 1969 में आरंभ हुए मुक्त विश्वविद्यालय से जोड़कर देखा जा सकता है जो कि महान सफलता सिद्ध हुई थी। आप जानते हैं (इकाई-1 देखें) कि अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा वर्ष (1970) के दौरान शिक्षा एवं सामाजिक कल्याण मंत्रालय ने सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग तथा यूनेस्को के साथ भारतीय राष्ट्रीय आयोग के सहयोग द्वारा दिसंबर 1970 में ''मुक्त विश्वविद्यालय'' पर

एक सेमिनार आयोजित किया था। इस सेमिनार में प्रायोगिक स्तर पर भारत में मुक्त विश्वविद्यालय की स्थापना की अनुशंसा की गई थी। इसके लिए भारत सरकार ने मुक्त विश्वविद्यालय के लिए आठ सदस्यों का कार्यसमूह गठित किया था जिसे जी. पार्थसारथी की अध्यक्षता में मुक्त विश्वविद्यालय के गठन के बारे में अपने विचार एवं अनुसंशाएं प्रस्तुत करनी थी। कार्यसमूह द्वारा ब्रिटेन के मुक्त विश्वविद्यालय पद्धति का गहन अध्ययन करने के पश्चात 1974 में भारत में मुक्त विश्वविद्यालय को स्थापित करने की संभावनाओं के बारे में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की थी जिसमें यह अनुशंसा की गई थी कि,

> "भारत सरकार को, जितना जल्दी संभव हो सके, संसद द्वारा पारित कानून के माध्यम से एक मुक्त विश्वविद्यालय की स्थापना करनी चाहिए। इस विश्वविद्यालय का कार्यक्षेत्र संपूर्ण देश में फैला होना चाहिए ताकि अब यह पूर्ण रूप से विकसित हो जाए तब किसी भी विद्यार्थी, चाहे वह देश के किसी भी सुदूर क्षेत्र में हो, तक इस विश्वविद्यालय की शिक्षा एवं डिग्री की पहुँच हो।"

तदोपरांत केंद्र सरकार द्वारा राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय की स्थापना के लिए मसौदा तैयार किया गया, परंतु इस प्रक्रिया में विलंब हो गया। इसी बीच आंध्रप्रदेश सरकार के प्रयासों से राज्य मुक्त विश्वविद्यालय (आंध्र प्रदेश मुक्त विश्वविद्यालय) की स्थापना 1982 में हुई जिसे बादे में डॉ. भीमराव अंबेडकर मुक्त विश्वविद्यालय (BRAOU) का नाम दिया गया।

केन्द्र सरकार के पुनः प्रयासों से, स्वर्गीय प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी के नाम पर एक राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय 20 सितम्बर, 1985 को अस्तित्व में लाया गया। इग्नू अधिनियम (एक्ट), 1985 की प्रस्तावना में इग्नू के मुख्य उद्देश्य निम्नलिखित थेः

- राष्ट्र की शिक्षा व्यवस्था में मुक्त विश्वविद्यालय तथा दूरस्थ शिक्षा पद्धति को शुरू करना एवं बढ़ावा देना।
- ऐसे मुक्त विश्वविद्यालय पद्धति में विभिन्न मानकों को तय करना एवं समन्वय स्थापित करना।

वर्ष 1991 में, इग्नू ने दूरस्थ शिक्षा परिषद (DEC) की स्थापना की ताकि भारत में मुक्त विश्वविद्यालय तथा दूरस्थ शिक्षा पद्धति के संबंध में मानकों को तय किया जा सके एवं इस संदर्भ में गुणवत्ता को बढ़ावा देते हुए समन्वय स्थापित किया जा सके।

वर्तमान स्थिति

BRAOU तथा IGNOU की सफलता से प्रेरित होकर, अन्य राज्यों जैसे राजस्थान, बिहार, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, गुजरात, कर्नाटक और अन्य राज्यों ने मुक्त विश्वविद्यालयों की स्थापना की। अतः 1982 से लेकर अब तक, हमारे देश में कुल 15 मुक्त विश्वविद्यालय हैं जो पिछले 35 वर्षों में स्थापित हुए हैं। यह विश्वविद्यालय निम्नलिखित हैंः

राष्ट्रीय स्तर : इंदिरा गाँधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय (इग्नू), नई दिल्ली (1985)

राज्य स्तरः

1) डॉ. बी. आर. अंबेडकर मुक्त विश्वविद्यालय (BRAOU), हैदराबाद (आ.प्र.), (1982)।
2) नालंदा मुक्त विश्वविद्यालय, पटना, बिहार (1982)।
3) कोटा मुक्त विश्वविद्यालय, कोटा, राजस्थान (1987)।
4) यशवंत राव चव्हाण महाराष्ट्र मुक्त विश्वविद्यालय, नासिक, महाराष्ट्र (1989)।

5) मध्य प्रदेश भोज मुक्त विश्वविद्यालय, भोपाल, म.प्र. (1992)।

6) डॉ. बाबा साहेब अंबेडकर मुक्त विश्वविद्यालय, अहमदाबाद, गुजरात (1994)।

7) कर्नाटक राज्य मुक्त विश्वविद्यालय, मैसूर (1996)।

8) नेताजी सुभाष चंद्र बोस मुक्त विश्वविद्यालय, कलकत्ता, पश्चिम बंगाल (1997)।

9) उत्तर प्रदेश राजर्षि टंडन मुक्त विश्वविद्यालय, इलाहाबाद, उत्तर प्रदेश (1999)।

10) तमिलनाडु मुक्त विश्वविद्यालय, चेन्नई, तमिलनाडु (2002)।

11) पं. सुंदर लाल शर्मा मुक्त विश्वविद्यालय, बिलासपुर, छत्तीसगढ़ (2004)।

12) उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय, हल्द्वानी (नैनीताल), (2005)।

13) कृष्ण कांत हांडिक राज्य मुक्त विश्वविद्यालय, गुवाहाटी, असम (2005)।

14) ओडिशा राज्य मुक्त विश्वविद्यालय, संबलपुर, ओडिशा (2015)।

भारत में मुक्त शिक्षा पद्धति पर इग्नू का गहरा प्रभाव है। मुक्त विश्वविद्यालय पद्धति का वर्तमान में दूरस्थ शिक्षा में अद्वितीय स्थान है जो कि इसके स्वायत्त प्रकृति के कारण है। मुक्त विश्वविद्यालय की अनुदेशात्मक व्यवस्था में स्व-अनुदेशी बहु-माध्यम पैकेज, गहन विद्यार्थी सहायक सेवाओं के लिए सुविधाएं, वीडियो फिल्म, शैक्षिक दूरदर्शन, टेलीकॉफ्रेंसिंग, वीडियों कॉफ्रेंसिंग, कंप्यूटर नेटवर्किंग इत्यादि आधुनिक सूचना एवं संप्रेषण प्रौद्योगिकी का व्यापक उपयोग सम्मिलित हैं।

इग्नू के राष्ट्रीय स्तर का विश्वविद्यालय होने के कारण, इसका क्षेत्रीय केंद्रों एवं अध्ययन केंद्रों का सबसे बड़ा जाल है जो कि इसके विभिन्न शैक्षिक कार्यक्रमों में नामांकित विद्यार्थियों को प्रभावी ढंग से सहायक सेवाएं प्रदान करने के लिए स्थापित किए गए हैं। उदाहरण के लिए 2011 तक जब इग्नू अपनी स्थापना की व रजत जयंती मना रही थी, तब इसका प्रारूप निम्न ढंग से था (तालिका 3.1 देखें)

तालिका 3.1: इग्नू एक नजर में

पहलू/पक्ष	संख्या
विद्यापीठ	21
प्रभाग/खंड	12
पीठ	5
केन्द्र	8
संस्थान	5
क्षेत्रीय केंद्र	67
अध्यापक एवं एकेडमिक स्टाफ	538
प्रशासनिक स्टाफ	1,303
विद्यार्थी सहायता सेवा केंद्र	3,252
पूर्वोत्तर शैक्षिक विकास परियोजना (क्षेत्रीय केंद्र)	9
विद्यार्थी सहायता केंद्र	552

विदेशी विद्यार्थी सहायता सेवा केंद्र	70
विदेशी विद्यार्थी नामांकन	43,500
शैक्षणिक परामर्शदाता	48,000
पी.एच.डी. कार्यक्रम	49
शैक्षणिक कार्यक्रम	511
ऑनलाइन कार्यक्रम	27
सामुदायिक महाविद्यालय	258
परिसर आधारित कार्यक्रम	26
ऑनलाइन अध्ययन सामग्री (मुक्त स्रोत)	95% (कुल)
एक्टिव रजिस्टर्ड यूजर रिपॉजिटरी (OER)	60,000
2011 में पंजीकृत विद्यार्थी	8.6 लाख
कुल नामांकित विद्यार्थी	2.9 मिलियन
2011 में प्रदत्त डिग्री, डिप्लोमा एवं सर्टिफिकेट	1.5 मिलियन
कोर्स सामग्री की संख्या	1,62,99,063
दृश्य-श्रव्य कार्यक्रम	3,718
2011-12 में सत्रांत परीक्षा में उपस्थित विद्यार्थी	28,73,147
201-12 में डिग्री प्राप्त करने वाले विद्यार्थी	14,80,393
मोबाइल एस.एम.एस. अलर्ट की सुविधा	संपूर्ण भारत
कैदियों के लिए निःशुल्क शिक्षा	4,110 (भारतीय जेलों में)

स्रोतः 1) इग्नू प्रोफाइल 2011, इग्नू, नई दिल्ली, अगस्त 2011

2) 24वां दीक्षांत समारोहः उपकुलपति रिपोर्ट, इग्नू, सितंबर, 2011

अन्य मुक्त विश्वविद्यालयों (राज्य मुक्त विश्वविद्यालयों) ने भी अपने क्षेत्रीय केंद्रों, अध्ययन केंद्रों इत्यादि को अपने-अपने राज्यों या अपने क्षेत्राधिकार में स्थापित किये हैं। अतः भारत में मुक्त विश्वविद्यालयों ने क्षेत्रीय केंद्रों एवं अध्ययन केंद्रों का व्यापक तंत्र स्थापित किये हैं।

इसके साथ ही, इन विश्वविद्यालयों ने इग्नू की दूरस्थ शिक्षा परिषद् (DEC, 2012 से यूजीसी के तहत वर्तमान दूरस्थ शिक्षा ब्यूरो के पूर्वर्ती) के अंतर्गत सहायता संघ उपागम को अपनाया है ताकि अध्ययन सामग्री, इलैक्ट्रॉनिक मीडिया आधारित सहयोग, टेलीकांफ्रेसिंग तथा विश्वविद्यालय स्तर पर अन्य सुविधाओं/संसाधनों को साझा किया जा सके। दुर्भाग्य से सहायता संघ उपागम पूर्ण आकार नहीं ले पाया तथा इसकी जड़ें मजबूत नहीं हो पाई ताकि दूरस्थ शिक्षा को अधिक मुक्त एवं लचीला बनाया जा सके जिससे इसकी पहुँच अधिक से अधिक विद्यार्थियों तक बेहतर संभव तरीकों से हो सके।

अपनी प्रगति जाँचें

टिप्पणी : क) अपने उत्तर को नीचे दिए गए खाली स्थान में लिखिए।

ख) इकाई अंत में दिए "अपनी प्रगति जाँचें" प्रश्नों के उत्तर से अपने उत्तर की तुलना कीजिए।

1) भारत में कितने मुक्त विश्वविद्यालय हैं? उनके नाम लिखिए।

.....

.....

.....

.....

.....

3.2.3 मुक्त विद्यालय

जैसा कि इकाई-1 (भाग 1.2.2) में कहा जा चुका है कि विद्यालय स्तर पर दूरस्थ शिक्षा की शुरूआत, विश्वविद्यालय स्तर पर इसकी शुरूआत के बाद हुई। विद्यालय स्तर पर दूरस्थ शिक्षा को आरंभ करने का विचार 1964 में माध्यमिक शिक्षा बोर्डों के कांफ्रेंस की सिफारिशों के आधार पर आया। राष्ट्रीय शिक्षा नीति, 1968 ने इस विचार को और अधिक बढ़ावा दिया। स्कूल स्तर पर दूरस्थ शिक्षा को शुरू करने का मुख्य उद्देश्य विद्यालय छोड़ने वाले विद्यार्थियों/बाहरी विद्यार्थियों को माध्यमिक/उच्च माध्यमिक स्तर की परीक्षा में भाग लेने के अवसर प्रदान करना था। 1970 के आरंभ तक विभिन्न राज्यों के माध्यमिक शिक्षा बोर्डों ने पत्राचार के माध्यम से दिल्ली, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, ओडिशा तथा मध्य प्रदेश में कोर्स आरंभ कर दिए थे।

एन.सी.ई.आर.टी. द्वारा अगस्त 1974 में मुक्त विद्यालय स्थापित करने की संभावनाओं को तलाशने के लिए एक कार्यसमूह गठित किया गया। नवंबर 1978 में CBSE और NCERT ने मुक्त विद्यालय पर अंतर्राष्ट्रीय सेमिनार आयोजित किया। इन संस्थाओं की अनुशंसाओं के आधार पर CBSE ने जुलाई 1979 में मुक्त विद्यालय की स्थापना की। 1989 में मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय की स्थापना की तथा मुक्त विद्यालय को उसमें समाहित कर दिया गया। साथ ही 1991 में आंध्र प्रदेश मुक्त विद्यालय की स्थापना हुई। 1995-96 में किए गए प्रयासों के कारण उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश तथा राजस्थान में मुक्त विद्यालयों की स्थापना हुई। बाद में राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय द्वारा भारत में राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय संघ National Consortium of Open School in India – NCOS) को भी स्थापित किया गया।

राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय का मुख्य उद्देश्य, सामान्य शिक्षा के कोर्स एवं कार्यक्रम, जीवन संवर्धन मॉड्यूल तथा व्यावसायिक कोर्स के माध्यम से इच्छुक विद्यार्थियों को सतत एवं विकासपूरक शिक्षा के अवसर प्रदान करना है। इसका मुख्य उद्देश्य यह भी है कि दूरस्थ शिक्षा व्यवस्था तथा मुक्त विद्यालयों में अधिगम स्तर की पहचान करना तथा बढ़ाना भी है।

राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय, विभिन्न स्तरों पर विभिन्न शैक्षिक कोर्स/कार्यक्रम आयोजित करता है। उदाहरण के लिए, सेतु कार्यक्रम (उनके लिए जो पांचवी कक्षा उत्तीर्ण हों), माध्यमिक कोर्स, उच्च माध्यमिक कोर्स, व्यावसायिक तथा जीवन संवर्धन कोर्स तथा विशेष प्राथमिकता

वाले समूहों के लिए अन्य कोर्स। राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय द्वारा शिक्षा, मुद्रित सामग्री, दृश्य-श्रव्य कार्यक्रम तथा व्यक्तिगत संपर्क कार्यक्रमों द्वारा प्रदान की जाती है। पूरे देश में विभिन्न सेवाएं जैसे नामांकन, व्यक्तिगत संपर्क कार्यक्रमों का आयोजन, विद्यार्थियों का निर्देशन एवं परामर्श, अध्ययन सामग्री का आवंटन तथा मूल्यांकन गतिविधियों को आयोजित करने के लिए राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय मान्यता प्राप्त संस्थानों की सहायता प्राप्त करता है।

स्कूल स्तर पर अन्य दूरस्थ शिक्षा संस्थान जो केवल माध्यामिक शिक्षा पर ही केंद्रित रहते हैं, आंध्र प्रदेश मुक्त विद्यालय प्रारंभिक शिक्षा पर बल देता है। आंध्र प्रदेश मुक्त विद्यालय परियोजना, औपचारिक विद्यालय छोड़ने वाले बच्चों को प्रोत्साहित करता है तथा उन्हें विद्यालय में वापस लाने का प्रयास करता है ताकि गांव के सभी बच्चों को शैक्षणिक सहायता प्रदान की जा सके। इस परियोजना में राज्य में चुने हुए जिलों के गांवों पर ही ध्यान केंद्रित किया जाता है। इस परियोजना के अंतर्गत विद्यार्थियों की सुविधानुसार, ग्रामीण केंद्र पर मुद्रित तथा श्रव्य सामग्री तथा अनुदेशक-निर्देशित गतिविधियों पर आधारित अधिगम मॉड्यूल प्रदान किए जाते हैं।

अन्य राज्यों में पत्राचार शिक्षा कार्यक्रम माध्यमिक स्कूल छोड़ने वाले बच्चों को शिक्षा के अवसर प्रदान करते हैं जैसे उत्तर प्रदेश में उच्च माध्यमिक स्तर पर। यह मुक्त विद्यालय राज्य माध्यमिक शिक्षा बोर्ड द्वारा सुझाए गए पाठ्यक्रम को ही पढ़ाते हैं तथा मुद्रित सामग्री को ही शिक्षण का प्रमुख माध्यम मानते हैं। उनमें सत्रीय कार्य (assignments) तथा व्यक्तिगत संपर्क कार्यक्रमों का भी प्रावधान होता है।

बाद में राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय को राष्ट्रीय मुक्त विद्यालयी संस्थान (NIOS) का नाम दिया गया। इसका मुख्य उद्देश्य सभी को विशेषकर लड़कियाँ एवं महिलाएं, ग्रामीण युवक, कामकाजी महिला एवं पुरूष, अनुसूचित जाति एवं जनजाति, विभिन्न योग्यताओं वाले व्यक्ति तथा अन्य वंचित व्यक्तियों, जो किन्हीं कारणों से अपनी शिक्षा पूरी नहीं कर पाए थे, को शिक्षा प्रदान करना है। एन.आई.ओ.एस. द्वारा पूरे देश में विभिन्न जेलों में स्थापित अध्ययन केंद्रों के माध्यम से कैदियों को शिक्षा प्रदान करने के प्रयास किए गए हैं जिसमें उनसे फीस भी नहीं ली जाती है। एन.आई.ओ.एस., भारत, नेपाल तथा मध्य पूर्व के देशों में स्थित 20 क्षेत्रीय केंद्रों, दो उप-क्षेत्रीय केंद्रों, एक उप-क्षेत्रीय प्रकोष्ठ तथा 6,620 मान्यता प्राप्त संस्थानों एवं मान्यता प्राप्त व्यावसायिक संस्थानों, जिन्हें अध्ययन केंद्र के नाम से जाना जाता है, के तंत्र के माध्यम से कार्य करता है। (NIOS प्रोस्पैक्टस 2016-17)।

NIOS, तीन राष्ट्रीय शिक्षा बोर्ड में से एक है। दो अन्य शिक्षा बोर्ड हैं; केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (CBSE) तथा भारतीय स्कूल प्रमाणपत्र परीक्षा परिषद् (CISCE), NIOS में पूर्व में अर्जित ज्ञान को महत्त्व दिया जाता है और इसके लिए किसी अंतर्राष्ट्रीय, राष्ट्रीय तथा राज्य स्कूल बोर्ड या राज्य मुक्त विद्यालय की परीक्षा में उत्तीर्ण किन्हीं दो विषयों के क्रेडिट को NIOS द्वारा जोड़ लिया जाता है। वर्ष 2016 तक NIOS का स्वरूप निम्न प्रकार से था।

- विश्व का सबसे बड़ा मुक्त विद्यालय पद्धति जिसकी पिछले पाँच वर्षों में कुल नामांकन 2.78 मिलियन था।
- 1991 तक माध्यमिक, उच्च माध्यमिक तथा व्यावसायिक शिक्षा में 3.30 मिलियन विद्यार्थियों को प्रमाणीकृत किया गया।
- वर्ष 2014-15 में विभिन्न कोर्सों में 5,52,000 विद्यार्थियों को दाखिल किया गया।
- भारत और बाहरी देशों में स्थित 20 क्षेत्रीय केंद्रों, दो उप-क्षेत्रीय केंद्रों तथा 6,620 से अधिक अध्ययन केंद्रों के माध्यम से जनता तक पहुँच।

- शिक्षा को मुक्त एवं दूरस्थ शिक्षण के माध्यम एवं विभिन्न माध्यमों जैसे स्व-अनुदेशन मुद्रित सामग्री, दृश्य-श्रव्य एवं व्यक्तिगत संपर्क कार्यक्रमों के द्वारा शिक्षण प्रदान करना। इसके साथ ही रेडियो एवं टी.वी. कार्यक्रमों तथा मुक्त विद्यावाणी (NIOS की वेबसाइट द्वारा इंटरनेट पर श्रव्य कार्यक्रम) का भी सहारा लिया जाता है।

3.2.4 अध्यापक शिक्षा

शिक्षा आयोग (1964-66) ने विज्ञान और तकनीकी के क्षेत्र में तथा दूरदराज के क्षेत्रों में कार्यरत अध्यापकों के व्यावसायिक विकास के लिए पत्राचार के माध्यम से कोर्स आरंभ करने की अनुशंसा की थी। वर्ष 1967 में उस समय के सोवियत संघ के पत्राचार माध्यम द्वारा चलाए जा रहे कोर्सों का अध्ययन करने के लिए विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (UGC) ने प्रथम प्रतिनिधिमंडल भेजा था। इस प्रतिनिधिमंडल ने इस व्यवस्था को सीमित आधार पर अपनाने की अनुशंसा की थी ताकि पूर्व के अप्रशिक्षित अध्यापकों, जो कि पहले से ही नियमित सेवाएं दे रहे हैं तथा अलग-अलग योग्यताओं वाले प्रशिक्षित अध्यापकों का व्यावसायिक विकास किया जा सके। राष्ट्रीय शिक्षा नीति, 1968 में भी इन विचारों को बल देते हुए लिखा गया कि,: "विश्वविद्यालय स्तर पर अंशकालिक शिक्षा एवं पत्राचार कोर्स, अधिक से अधिक विकसित किए जाने चाहिए। ऐसी सुविधाएं, माध्यमिक विद्यालय के विद्यार्थियों, अध्यापकों, और कृषि, उद्योग तथा अन्य कर्मियों के लिए भी विकसित की जानी चाहिए।" (भारत सरकार, 1968)।

शिक्षा आयोग की संस्तुतियों तथा विश्वविद्यालय अनु. आयोग (UGC) प्रतिनिधिमंडल की रिपोर्ट के आधार पर गहन चर्चाएँ की गई। इसके बाद एन.सी.ई.आर.टी. ने 1967 में अपने चार क्षेत्रीय शिक्षा महाविद्यालयों जो अजमेर, भोपाल, भुवनेश्वर तथा मैसूर में स्थित हैं, के माध्यम से अप्रशिक्षित अध्यापकों को पत्राचार के माध्यम से बी.एड. कोर्स शुरू किया। तदोपरांत इन महाविद्यालयों का परिदृश्य बदला। विभिन्न मुक्त विश्वविद्यालयों तथा दोहरी व्यवस्था वाले विश्वविद्यालयों के पत्राचार शिक्षा निदेशालयों के माध्यम से बी.एड. करने की भारी होड़ मच गई। वर्ष 1995-96 में, 13 विश्वविद्यालय पत्राचार शिक्षा माध्यम से तथा 3 राज्य मुक्त विश्वविद्यालय दूरस्थ शिक्षा के माध्यम से बी.एड. कोर्स प्रदान कर रहे थे। इन विश्वविद्यालयों में, आंध्र, अन्नामलाई, भोपाल, बैरहमपुर, काकतीय, कश्मीर, कुरूक्षेत्र, महर्षि दयानंद, मदुरई कामराज, मैसूर, ओस्मानिया, शिवाजी, श्री वैंकटेश्वरा, बाबा साहेब अंबेडकर मुक्त विश्वविद्यालय (गुजरात), यशवंत राव चव्हाण महाराष्ट्र मुक्त विश्वविद्यालय (महाराष्ट्र) तथा कोटा मुक्त विश्वविद्यालय (राजस्थान) शामिल थे। वर्ष 2000 में, इग्नू ने अप्रशिक्षित सेवारत अध्यापकों को बी.एड. कोर्स करवाने के लिए राष्ट्रीय स्तर पर शुरूआत की।

राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद (NCTE), 1996 के दिशा निर्देशों के परिणामस्वरूप, पत्राचार कोर्स संस्थानों/ पत्राचार शिक्षा निदेशालयों ने बी.एड. कोर्स की शुरूआत की। वर्ष 1996-97 के दौरान UGC, NCTE तथा DEC की संयुक्त समिति की अनुशंसों पर दूरस्थ शिक्षा के माध्यम से बी.एड. कोर्स में सुधार किए गए। अतः इसके अनुसार राज्य मुक्त विश्वविद्यालयों ने अपने-अपने राज्य में 1997 में बी.एड. कोर्स की शुरूआत की। वर्ष 1997 में UGC ने भी पत्राचार के माध्यम से बी.एड. कोर्स शुरू करने के लिए नियम बनाए।

बी.एड. कार्यक्रम के अतिरिक्त, कुछ विश्वविद्यालयों द्वारा पत्राचार एवं दूरस्थ शिक्षा के माध्यम से एम.एड. कार्यक्रम आरंभ किया गया। इन विश्वविद्यालयों में, आंध्र, अन्नामलाई, हिमाचल प्रदेश, कुरूक्षेत्र, मदुरई कामराज, ओस्मानिया, पंजाब, कोटा मुक्त विश्वविद्यालय एवं इग्नू शामिल थे। इग्नू तथा अंग्रेजी एवं विदेशी भाषा केंद्रीय संस्थान (CIEFL), हैदराबाद द्वारा भी देश में विश्वविद्यालय/ महाविद्यालय अध्यापकों तथा स्कूल स्तर पर

अध्यापकों के व्यावसायिक विकास के लिए दूरस्थ शिक्षा के माध्यम से कोर्स शुरू किए गए थे। कुछ राज्यों जैसे मध्य प्रदेश ने अप्रशिक्षित प्राथमिक विद्यालय शिक्षकों के लिए दूरस्थ शिक्षा कार्यक्रमों के माध्य से सर्टिफिकेट कोर्स शुरू किए थे। केंद्रीय शिक्षा तकनीकी संस्थान (CIET) तथा इग्नू के संयुक्त तत्वाधान में वर्ष 1996 में टेलीकांफ्रेंसिंग के माध्यम से प्राथमिक विद्यालय शिक्षकों को सेवाकालीन उन्मुखीकरण का प्रयोग दूरस्थ शिक्षा के माध्यम से प्राथमिक शिक्षक प्रशिक्षण की दिशा में ऐतिहासिक घटना सिद्ध हुआ। जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम (DPEP) में इग्नू ने प्राथमिक विद्यालय शिक्षकों को टेलीकांफ्रेंसिंग के माध्यम से क्षेत्रीय भाषाओं में सतत् उन्मुखीकरण देने के लिए देशव्यापी परियोजना की शुरूआत की।

शिक्षा प्रणाली के विभिन्न स्तरों जैसे पूर्व-प्राथमिक, प्राथमिक, माध्यमिक, वरिष्ठ माध्यमिक और उच्च स्तर पर अध्यापकों की व्यावसायिक विकास एवं योग्यता निर्माण के लिए अध्यापक शिक्षा में चलाए जा रहे एम.एड, बी.एड, डिप्लोमा तथा सर्टिफिकेट कार्यक्रमों से इग्नू भारत में अध्यापक शिक्षा कार्यक्रमों को प्रदान करने वाला मुख्य प्रदाता बन गया है। वर्तमान में इग्नू ने जुलाई 2016 से अपना संशोधित बी.एड. कार्यक्रम शुरू किया है जो NCF 2005, NCFTE, 2009 तथा राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् (NCTE) के 2014 के नियमों के अनुसार विकसित किया गया है।

3.3 समस्याएँ एवं चुनौतियाँ

जैसा कि आपने जाना कि मुक्त एवं दूरस्थ शिक्षा ने शिक्षा की कुछ समस्याओं एवं चुनौतियों को हल करने में योगदान दिया है। परंतु मुक्त एवं दूरस्थ शिक्षा स्वयं भी विभिन्न प्रकार की समस्याओं एवं चुनौतियों से जूझ रही है। आइए, इन्हें एकल पद्धतीय एवं द्विपद्धतीय विश्वविद्यालयों के संदर्भ में समझने का प्रयास करें।

3.3.1 द्विपद्धतीय विश्वविद्यालय

जैसा कि आप जानते हैं कि दिल्ली विश्वविद्यालय, पहला विश्वविद्यालय था जिसने 1962 में पत्राचार के माध्यम से कोर्स शुरू करने का प्रयोग किया था जो कि विशेषज्ञ समिति द्वारा 1961 में दी गई रिपोर्ट के आधार पर था। बाद में दिल्ली विश्वविद्यालय ने एक उपसमिति का गठन किया ताकि प्रथम डिग्री स्तर पर विभिन्न कोर्स शुरू करने के लिए सुझाव दिए जा सकें। इस विश्वविद्यालय के दूरस्थ शिक्षा कार्यक्रमों की सफलता ने अन्य विश्वविद्यालयों तथा राष्ट्रीय महत्त्व वाले संस्थानों को पत्राचार के माध्यम से विभिन्न प्रकार के कार्यक्रम आरंभ करने के लिए प्रेरित किया।

इसी दौरान UGC ने पत्राचार माध्यम से कोर्सों को एकरूप बनाने के लिए दिशा निर्देश तैयार करने का प्रयास किया। शिक्षा मंत्रालय, भारत सरकार ने लगातार, 1967, 1968 तथा 1971 में तीन प्रतिनिधिमंडलों का गठन किया तथा उन्हें तत्कालीन सोवियत संघ में पत्राचार शैक्षिक कार्यक्रमों का अध्ययन करने के लिए भेजा। वर्ष 1969 में UGC ने पत्राचार कार्यक्रमों के लिए दिशानिर्देश जारी किए। इसके अनुसार पत्राचार पाठ्यक्रमों का मुख्य उद्देश्य निम्नलिखित को शिक्षा के अवसर प्रदान करना था:

- आर्थिक या अन्य कारणों से जिन विद्यार्थियों ने औपचारिक शिक्षा छोड़ दी थी।
- भौगोलिक रूप से दूरदराज क्षेत्रों के विद्यार्थी।
- ऐसे विद्यार्थी जिन्होंने अभिप्रेरणा या रूझान की कमी के चलते शिक्षा छोड़ दी लेकिन बाद में वे प्रेरित हो गए।

- ऐसे विद्यार्थी जिन्हें नियमित महाविद्यालय या विश्वविद्यालय में प्रवेश नहीं मिला या वे प्रवेश नहीं लेना चाहते थे हालाँकि उनके पास उच्च शिक्षा के लिए आवश्यक योग्यता है।
- ऐसे व्यक्ति जो शिक्षा को जीवन पर्यन्त गतिविधि मानते हैं तथा अपने ज्ञान को अद्यतन करना चाहते हैं या नए क्षेत्र में ज्ञान अर्जित करना चाहते हैं। (UGC, 1988)

उपरोक्त विकास के कारण, बहुत सारे विश्वविद्यालयों ने विभिन्न विषयों में डिग्री, डिप्लोमा तथा प्रमाणपत्र वाले कोर्स की शुरूआत की। ये विश्वविद्यालय, देश के सभी क्षेत्रों जैसे पूर्व, पश्चिम, उत्तर तथा दक्षिण में स्थित हैं। मार्च 2015 तक विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के दूरस्थ शिक्षा ब्यूरो (2014 तक दूरस्थ शिक्षा परिषद्) द्वारा अनुमोदित किए गए द्विपद्धतीय विश्वविद्यालय भारत में कुल 210 थे जो पिछले चालीस वर्षों (1968-2015) के दौरान विकसित हुए ताकि दूरस्थ शिक्षा कार्यक्रम शुरू किए जा सकें।

समस्याएँ एवं चुनौतियाँ

इन विश्वविद्यालयों तथा संस्थानों की दूरस्थ शिक्षा ईकाइयाँ दो पद्धतियों से चलती रहीं अर्थात परिसर में विद्यमान नियमित तथा पत्राचार/दूरस्थ शिक्षा कार्यक्रम बढ़ती हुई प्रतिस्पर्धा के परिणामस्वरूप, कुछ संस्थान जैसे क्षेत्रीय शिक्षा महाविद्यालयों ने इन कोर्सों को बंद कर दिया था। राजस्थान और कर्नाटक राज्यों में पारंपरिक विश्वविद्यालयों जैसे राजस्थान, उदयपुर तथा मैसूर इत्यादि ने राज्य मुक्त विश्वविद्यालयों की स्थापना के कारण अपने दूरस्थ शिक्षा कार्यक्रमों को बंद कर दिया था।

भारत में द्विपद्धतीय विश्वविद्यालयों/संस्थानों की मुख्य चुनौती यह है कि इन विश्वविद्यालयों में विद्यमान दूरस्थ शिक्षा की ईकाइयाँ नीति नियोजन, प्रशासन, प्रबंधन, पाठ्यक्रम विकास, विद्यार्थी सहयोग, गुणवत्ता निर्धारण, सूचना एवं संप्रेषण तकनीकी के उपयोग इत्यादि से संबंधित मुद्दों पर संपूर्ण रूप से स्वायत्त नहीं हैं। इसके अलावा, इनकी भावी चुनौती यह है कि द्विपद्धतीय विश्वविद्यालयों, एकल पद्धतीय विश्वविद्यालयों तथा मुक्त विश्वविद्यालयों में बढ़ती आपसी प्रतिस्पर्धा के कारण दूरस्थ शिक्षा कार्यक्रमों को कैसे आगे बढ़ाया जाए।

वर्तमान में द्विपद्धतीय संस्थानों तथा समर्पित दूरस्थ शिक्षा संस्थानों को शिक्षा की पहुँच वंचित वर्ग तक पहुँचाने के ध्येय को पूरा करने के लिए निरंतर प्रयास करते रहना चाहिए।

3.3.2 एकल पद्धतीय विश्वविद्यालय

अपनी स्वायत्त प्रकृति के कारण, मुक्त विश्वविद्यालय व्यवस्था का दूरस्थ शिक्षा के क्षेत्र में अद्वितीय स्थान है। मुक्त विश्वविद्यालयों में अनुदेशन के लिए स्व-अनुदेशन मुद्रित सामग्री तथा अन्य बहुमाध्यम मॉडयूल, व्यापक विद्यार्थी सहायता सेवाएँ के आधुनिक संचार प्रौद्योगिकी जैसे शिक्षक, टी वी टेलीकांफ्रेंसिंग, कंप्यूटर कांफ्रेंसिंग, इत्यादि का बहुतायत उपयोग करता है। इस तरह की अनुदेशन व्यवस्था या तो द्विपद्धतीय विश्वविद्यालयों में नहीं होती है या उनमें इसे इतना महत्त्व नहीं दिया जाता है। इस कारण से यह विश्वविद्यालय, मुक्त विश्वविद्यालयों से भिन्न होते हैं।

उपरोक्त भाग 3.2.2 में हमने भारत में मुक्त विश्वविद्यालयों के विकास के बारे में चर्चा की। आपने जाना कि आंध्र प्रदेश राज्य मुक्त विश्वविद्यालय के 1982 में स्थापना के बाद तथा 1985 में इग्नू के स्थापित होने के बाद आज तक देश में कुल 15 मुक्त विश्वविद्यालय हैं। यह मुक्त विश्वविद्यालय, एकल पद्धति के रूप में चले, लेकिन 2009-13 के दौरान इग्नू ने दोहरी प्रणाली अपनाई जब इसने दूरस्थ शिक्षा कार्यक्रमों के साथ-साथ परिसर में कुछ

नियमित कार्यक्रम भी चलाए। आप 2011 तक इग्नू के विभिन्न पहलूओं के बारे में जान चुके हैं। बाद में इग्नू पुनः एकल पद्धति वाले विश्वविद्यालय में परिवर्तित हुई तथा केवल दूरस्थ शिक्षा के माध्यम से ही कार्यक्रम चलाने लगी जो वर्तमान में भी उसी प्रकार से चल रहे हैं।

मुक्त एवं दूरस्थ शिक्षा ने भारत में उच्च शिक्षा में गुणवत्ता, समता तथा समानता के अवसरों को बढ़ाते हुए मानव संसाधनों के विकास में एक ऐतिहासिक भूमिका निभाई है। केवल 11वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान केवल इग्नू, राज्य मुक्त विश्वविद्यालय तथा दूरस्थ शिक्षा संस्थानों का नामांकन में क्रमशः 6.97 लाख, 3.03 लाते तथा 9.28 लाख का योगदान था। उच्च शिक्षा में कुल नामांकन का 12.15% दूरस्थ शिक्षा संस्थानों का था जिसमें से 45.39% नामांकन लड़कियों/महिलाओं का था (भारत सरकार, 2015)।

समस्याएँ एवं चुनौतियाँ

केवल शिक्षा तक पहुँच ही काफी नहीं है। बहुत दूरस्थ शिक्षा लेखकों एवं शोधकर्त्ताओं ने 'मुक्त द्वार बनाम भ्रमणशील द्वार' स्थिति को वर्णित किया है जो तब घटित होती है जब संस्थान सभी विद्यार्थियों को नामांकित कर लेते हैं परंतु उन्हें सफलता प्राप्त करने के लिए सहायता प्रदान नहीं करते हैं। यह आवश्यक नहीं है कि शिक्षा के मूल्य-संवर्धित अवधारणा का समर्थन किया जाए, परंतु मान्यता के लिए एक याचिका है की दूरस्थ माध्यम से प्रौढ़ शिक्षा की विशेष आवश्यकताएं हैंः अधिगम नियोजन, नामांकन एवं पंजीकरण सहायता, महिलाओं को वित्तीय सहायता, विशेषकर शैक्षिक जगत में पुनःप्रवेश करने वाली समन्वयक ईकाई पुस्तक भंडार, पुस्तकालय तथा अनुदेशनात्मक मीडिया केन्द्र से आवश्यक सामग्री तक पहुँच, स्रोत से समयानुसार सही सूचना, कार्यक्रम हेतु सतत् एवं उचित शैक्षणिक परामर्श एवं विद्यार्थियों की आवश्यकतानुसार पाठ्यक्रम सामग्री के साथ शिक्षण बल्कि संस्थान की सुविधा के अनुसार नहीं (http://web.worldbank.org/archive/website00236B/61EB/UNI_03.HTM)।अतः केवल उत्तम गुणवत्ता वाली कोर्स सामग्री तैयार कर लेने से मुक्त विश्वविद्यालयों द्वारा शिक्षा की गुणवत्ता की गारंटी नहीं दी जा सकती है। विद्यार्थी सहायक सेवाएं जैसे विद्यार्थियों को पाठ्यक्रम सामग्री का वितरण, विद्यार्थियों को सही समय पर प्रतिपुष्टि प्रदान करना, परामर्श आयोजन, मल्टी-मीडिया का उपयोग, परीक्षाओं का आयोजन, एवं समय पर परीक्षा परिणाम की घोषणा इत्यादि एकल व्यवस्था वाले विश्वविद्यालयों के लिए मुख्य चुनौतियाँ हैं जो मुद्रित सामग्री को अनुदेशन के मुख्य माध्यम के रूप में अपनाते हैं। इन सभी पहलूओं का विद्यार्थियों की धारण दर तथा उत्तीर्णता दर पर गहरा प्रभाव होता है। लक्ष्मी रेड्डी (2002) द्वारा इग्नू कार्यक्रमों पर किए गए व्यक्तिपरक अध्ययन में यह पाया गया कि पिछले 15 वर्षों में विभिन्न कार्यक्रमों में नामांकित विद्यार्थियों की औसत उत्तीर्णता दर केवल 8.85 प्रतिशत है। वास्तव में, इस संदर्भ में सभी एकल पद्धतीय (मुक्त) विश्वविद्यालयों को सुधार हेतु क्रियान्वयन की रणनीतियों को मजबूत करने की आवश्यकता है।

इसके अतिरिक्त सामान्यतः मुक्त एवं दूरस्थ शिक्षा तथा मुख्यतः इग्नू एवं राज्य मुक्त विश्वविद्यालयों की भावी चुनौतियाँ ही भारत में पूर्णतः मुक्त एवं दूरस्थ शिक्षा व्यवस्था के भविष्य को तय करेंगी। यह अधिकांशतः नीतियों तथा दिशा निर्देशों पर निर्भर करता है। 12वीं पंचवर्षीय योजना में भारत सरकार ने मुक्त एवं दूरस्थ शिक्षा को बहुत महत्त्व दिया है जो कि शिक्षा के क्षेत्र में इसके योगदान से संबंधित बनाई गई उच्च आकांक्षाओं में देखा जा सकता है (तालिका 3.2 देखें)।

वैश्विक स्तर पर मूक्स (MOOCS) के उद्य के कारण, भारत भी इसे अपनाने का प्रयास कर रहा है। इसके लिए भारत सरकार के स्वदेशी सूचना तकनीकी पर आधारित 'स्वयं'

(SWAYAM) प्लेटफार्म की सहायता ली जा रही है ताकि शिक्षा नीति के तीन आयामों–पहुँच, समता तथा गुणवत्ता– को प्राप्त किया जा सके। इस प्रयास का मुख्य उद्देश्य यह है कि वंचित विद्यार्थियों सहित सभी के लिए शिक्षण-अधिगम के सर्वोत्तम संसाधन उपलब्ध कराया जा सके। यह उन विद्यार्थियों के मध्य डिजिटल अंतर को कम करने का प्रयास है जो किन्हीं कारणों से डिज़िटल क्रांति से अछूते रहे हैं तथा ज्ञान आधारित अर्थव्यवस्था की मुख्यधारा में जुड़ नहीं पाए हैं। 'स्वयम' (SWAYAM) में करवाए जाने वाले कोर्स चार भागों में हैं – (1) वीडियो आधारित भाषण, (2) विशेष रूप से तैयार की गई पाठ्य सामग्री, जो डाउनलोड या मुद्रित किया जा सकता है, (3) स्व– मूल्यांकन परीक्षण, तथा (4) अपनी शंका–समाधान के लिए चर्चा करने हेतु ऑनलाईन चर्चामंच। इन अधिगम अनुभवों को रोचक एवं सशक्त बनाने के लिए दृश्य-श्रव्य सामग्री एवं मल्टी-मीडिया तकनीकी तथा अत्याधुनिक शिक्षण शास्त्र और प्रौद्योगिक का उपयोग किया जाता है। उच्च स्तर की गुणवत्तापरक सामग्री विकसित करने एवं वितरण हेतु सात राष्ट्रीय स्तर के समन्वयकों की नियुक्ति की गई है। यह सात समन्वयक हैं: अभियांत्रिकी के लिए NPTEL, स्नातकोत्तर शिक्षा के लिए UGC, स्नातक स्तर की शिक्षा के लिए CEC, विद्यालय शिक्षा के लिए NCERT तथा NIOS, विद्यालय से बाहर विद्यार्थियों के लिए IGNOU तथा प्रबंधन शिक्षा के IIM, बंगलूरू।

अब आप शायद मुक्त एवं दूरस्थ शिक्षा के क्षेत्र में किए गए प्रयासों के बारे में समझ चुके हैं जो निकट भविष्य में मुक्त ऑनलाईन शिक्षा की तरफ बढ़ रहा है। परंतु नेटवर्क कनेक्टिविटि तथा इसकी गुणवत्ता, उपलब्धता, खर्चीलापन/सस्तापन इत्यादि मुद्दे एवं चुनौतियों जो पाठ्यक्रम और विद्यार्थियों के परिप्रेक्ष्य से संबंधित है पर गहन ध्यान देने की आवश्यकता होगी।

हालाँकि स्थानीय स्तर पर अध्ययन केंद्रों के माध्यम से कुछ समस्याएँ हल हो सकती हैं परंतु इनको शुरूआत में स्थापित करने तथा आगे चलाने में आवश्यक धनराशि के अनुसार बहुत सारे विद्यार्थियों को एक अध्ययन केंद्र द्वारा यह सुविधा नहीं प्रदान की जा सकती है। आर्थिक रूप से कमजोर होने के कारण बहुत सारे लोग शिक्षा की इस सुविधा से वंचित रह जाएंगे क्योंकि उनके पास आवश्यक उपकरणों या स्रोतों की उपलब्धता नहीं होगी। इस स्थिति में क्या 'स्वयम' की पहुँच सभी लोगों तक हो पाएगी, यह भविष्य में बहुत बड़ी चुनौती होगी जिससे निपटना बहुत आवश्यक है।

अपनी प्रगति जाँचें

टिप्पणी : क) अपने उत्तर को नीचे दिए गए खाली स्थान में लिखिए।

ख) इकाई अंत में दिए "अपनी प्रगति जाँचें" प्रश्नों के उत्तर से अपने उत्तर की तुलना कीजिए।

2) भारत में एकल पद्धतीय तथा द्विपद्धतीय विश्वविद्यालयों की प्रमुख भावी चुनौती क्या है?

.....

.....

.....

.....

.....

3.4 सारांश

इस ईकाई में आपने मुक्त एवं दूरस्थ शिक्षा के भारतीय अनुभव के बारे में जाना। आपने यह समझा कि पिछले साढ़े पाँच दशकों में भारत में मुक्त एवं दूरस्थ शिक्षा संस्थानों ने अपनी उपस्थिति तथा योग्यता प्रदर्शित कैसे की। इस ईकाई में एकल एवं द्विपद्धतीय विश्वविद्यालयों के वर्तमान एवं भावी चुनौतियों पर भी चर्चा हुई जोकि हालाँकि इस देश में मुक्त एवं दूरस्थ शिक्षा का भविष्य बहुत सुनहरा है।

3.5 "अपनी प्रगति जाँचें" प्रश्नों के उत्तर

1) भारत में 15 मुक्त विश्वविद्यालय हैं : इग्नू, डॉ. बी. आर. अम्बेडकर मुक्त विश्वविद्यालय (हैदराबाद), नालंदा मुक्त विश्वविद्यालय, कोटा मुक्त विश्वविद्यालय, यशवंतराव चव्हाण महाराष्ट्र मुक्त विश्वविद्यालय, मध्य प्रदेश भोज मुक्त विश्वविद्यालय, डॉ. बाबा साहेब अंबेडकर मुक्त विश्वविद्यालय, कर्नाटक राज्य मुक्त विश्वविद्यालय, नेताजी सुभाष चंद्र बोस मुक्त विश्वविद्यालय, उत्तर प्रदेश राजर्षि टंडन मुक्त विश्वविद्यालय, तमिलनाडु मुक्त विश्वविद्यालय, पंडित सुंदरलाल शर्मा मुक्त विश्वविद्यालय, उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय, कृष्ण कांत हांडिक राज्य मुक्त विश्वविद्यालय, ओडिशा राज्य मुक्त विश्वविद्यालय।

2) भारत में एकल पद्धतीय एवं द्विपद्धतीय विश्वविद्यालयों की प्रमुख भावी चुनौती यह है कि विद्यार्थी सहायक सेवाओं की पहुँच एवं गुणवत्ता बढ़ाने के लिए किस प्रकार से समन्वय स्थापित हो तथा प्रतिस्पर्धा के दौर में कैसे आगे बढ़ा जाए।

3.6 संदर्भ ग्रंथ

Association of Indian Universities. (1997). *Handbook of Distance Education*, AIU, New Delhi.

Distance Education Council. (1995). *Open Universities in India*, IGNOU, New Delhi.

Government of India. (1986). Nat*ional Policy on Education* Ministry of Education, New Delhi.

Government of India. (2013). (See http://planningcommission.nic.in/plans/planrel/fiveyr/12th/ pdf/12fyp_vol3.pdf — Retrieved on 11-09-2016).

Government of India. (2015). *All India Survey on Higher Education (2013-2014).* Ministry of Human Resource Development, Department of Higher Education, New Delhi. (See http://aishe. nic.in/aishe/viewDocument.action?documentId=196).

http://planningcommission.nic.in/plans/planrel/fiveyr/12th/pdf/12fyp_vol3.pdf

http://web.worldbank.org/archive/website00236B/WEB/UNI_03.HTM — Retrieved on 22-04-2017.

http://www.university.careers360.com/articles/list-of-approved-distance-education-universities-in-india — Retrieved on 27-08-2016.

https://swayam.gov.in/About — Retrieved on 23-4-2017.

IGNOU. (1985). *IGNOU Act.* IGNOU, New Delhi.

IGNOU. (2011). *IGNOU Profile 2011*. IGNOU, New Delhi.

IGNOU. (2011). *24th Convocation: Vice-chancellor's Report.* IGNOU, New Delhi.

Lakshmi Reddy, M. V. (2002). Students' Pass Rates: A Case Study of Indira Gandhi National Open University Programmes. *Indian Journal of Open Learning.* Vol.11, No.1, January, pp.103-125. (See http://cemca.org.in/ckfinder/userfiles/Lakshmi%20Reddy_MV__0249. pdf).

NIOS. (2016). *Prospectus 2016-17.* Noida: NIOS. (See http://www.nos.org/media/documents/ prospectus/AcadProspectus_2016_17.pdf — Retrieved on 08-10-2016).

Suggested Readings

Commonwealth of Learning. (2003). Three Year Plan 2003-2006 Available at www.col.org/programmes/reporting/TYP_2003.pdf

Koul, B.N. (2000). "Dystopia to Utopia and Beyond: A Case for Distance Education (DE) in Small States" in Proceedings of the University of West Indies Small States Conference, 27-28 July 2000, Ocho Rios, Jamaica. Available at www.col.org/resources/publications/ SmallStates00/2_conf_proc_master.pdf

Rumble, G. (1992). "The competitive vulnerability of distance teaching universities" in Open Learning, Vol. 7, No. 2, June 1992.

Ryan, Y. and Stedman, L. (2002). The Business of Borderless Education: 2001 update Canberra: Department of Education, Training and Youth Affairs. Available at http://www.dest.gov.au/archive/highered/eippubs/eip02_1/eip02_1.pdf

Taylor, J. C. (1997). "A dual mode model of distance education: The University of Southern Queensland". Open Praxis, Vol. 2, 9-13. 23

Taylor, J. C. (2000). "New Millenium Distance Education", in The World of Open and Distance Learning (Eds V Reddy and S Manjulika), Viva Books Private Ltd, India (475-480), ISBN 81 7649 155 1.

UNESCO. (2002). Open and Distance Learning – Trends, Policy and Strategy Considerations. Paris: UNESCO.

3.7 इकाई अंत अभ्यास

इकाई अंत प्रश्न

आप अपनी रूचि के अनुसार एवं अपने लाभ हेतु इन प्रश्नों के विस्तृत उत्तर या संक्षिप्त उत्तर लिख सकते हैं। यह आपको परीक्षा में तैयारी के लिए सहायक हो सकते हैं।

1) भारत में उच्च शिक्षा के लोकतांत्रिकरण में मुक्त विश्वविद्यालय व्यवस्था के योगदान पर चर्चा करें। (1000 शब्द)

2) भारत में विद्यालयी शिक्षा तथा अध्यापक शिक्षा के लिए मुक्त एवं दूरस्थ शिक्षा का क्या योगदान रहा है? (1000 शब्द)

3) भारत में एकल तथा द्विपद्धतीय विश्वविद्यालयों की समस्याएँ एवं चुनौतियाँ क्या हैं? (1000 शब्द)

आलोचनात्मक टिप्पणी हेतु प्रश्न

1) आपके अनुसार भारत में मुक्त एवं दूरस्थ अधिगम के माध्यम से विद्यालयी एवं अध्यापक शिक्षा की क्या समस्याएँ एवं चुनौतियाँ हैं? इनके समाधान के लिए अपने सुझाव देने का प्रयास करें।

क्रियाकलाप

भारत में दूरस्थ माध्यम से अध्यापक शिक्षा प्रदान करने हेतु नियामक संस्था/संस्थाओं की भूमिका पर टिप्पणी लिखिए।

.....

.....

.....

.....

.....

ignou
THE PEOPLE'S
UNIVERSITY